बृहस्पतिवार, 5 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

कपिल देव का पाकिस्तान पर हमला

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

तापसी पन्नू की 'अस्सी' का ट्रेलर हुआ रिलीज

Page-05

विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत को रूसी सस्ते तेल की जगह महँगे वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर दबाव पड़ेगा, जिससे रिटेल ईंधन महँगा होने की संभावना बढ़ सकती है।

क्या महँगा होगा डीजल-पेट्रोल?

भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हुई है, खासकर तब जब अमेरिका और भारत के बीच हुए संभावित ट्रेड डील में रूस से तेल न खरीदने का मुद्दा सामने आया है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि अंतिम समझौता फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि आने वाले समय में ईंधन के दाम सीधे रूप से बढ़ेंगे या नहीं।उन्होंने एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसके असर का आंकलन तब तक सही से नहीं किया जा सकता जब तक ट्रेड डील को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। वित्त मंत्री ने यह भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री और सरकार देश के हित के विपरीत कोई कदम नहीं उठाएंगे।सीतारमण ने कहा कि इस समझौते के तहत कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी और देश का पेट्रोल-डीजल नीति तथा ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर तय की जाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद में पहले ही इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान दे दिया गया है और आगे की स्थिति डील फाइनल होने पर ही स्पष्ट होगी।विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत को रूसी सस्ते तेल की जगह महँगे वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर दबाव पड़ेगा, जिससे रिटेल ईंधन महँगा होने की संभावना बढ़ सकती है।डील फाइनल होने के बाद ही पेट्रोल-डीजल की भविष्य की कीमतों पर ठोस फैसला लिया जाएगा।

क्या रूस से तेल खरीदना बंद होगा?

अमेरिका पक्ष ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, लेकिन भारत की तरफ से इस बात पर अधिकृत घोषणा अभी नहीं आई है और सरकारी बयान में यह साफ किया गया है कि निर्णय राष्ट्रीय हित, कीमतों और आपूर्ति-संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। रूस भी यह कह चुका है कि भारत किसी भी सप्लायर से तेल खरीद सकता है और वह स्वतंत्र है। इसके चलते फिलहाल स्थिति पूरी तरह कूटनीतिक बातचीत और बाज़ार परिस्थितियों पर निर्भर बनी हुई है।

असम और बंगाल में चुनाव लड़ सकती है JMM! हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा संकेत

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि असम और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। यह बयान आगामी चुनावों के राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना सकता है।सोरेन ने कहा है कि JMM असम और बंगाल के आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है, जहां पार्टी का ऐतिहासिक जनाधार रहा है और जहां उनके पिता व दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ पुराना नाता जुड़ा है।उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसका पहला चरण उत्तरी-पूर्व और बंगाल जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाना है। इससे JMM की नई पहचान पैदा होने की संभावना जताई जा रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना

है कि JMM का यह रुख इंडिया गठबंधन के संभावित विस्तार और क्षेत्रीय दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने की दिशा में है।

पार्टी का दावा है कि वह आदिवासी, दलित, और पिछड़े समुदायों के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने का प्रयास करेगी।

मणिपुर में नई सरकार का गठन — खेमचंद सिंह बने मुख्यमंत्री

मणिपुर में लगभग एक वर्ष से लागू राष्ट्रपति शासन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ-ग्रहण समारोह में खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री पद की "पद एवं गोपनीयता" की शपथ दिलाई। साथ ही नेमचा किपगेन और लोसी डिखो को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिसमें किपगेन मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बनीं। को बुधवार, 4 फरवरी 2026 को अधिकारिक रूप से हटाया गया, और उसके तुरंत बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।यह राजनीतिक बदलाव राष्ट्रपति शासन के हटने के ठीक बाद हुआ, जिसे 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था और लगभग 11 महीने 25 दिन तक जारी रहा। राष्ट्रपति डॉ. द्रौपदी मुर्मु के पूर्वाह्न नोटिफिकेशन के माध्यम से यह शासन समाप्त किया गया।भाजपा के वरिष्ठ नेता खेमचंद सिंह को एनडीए विधायक दल ने नेता के रूप में चुना, जिसके बाद उन्होंने मणिपुर के राष्ट्रपति

शासन हटते ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। एनडीए के समर्थन से भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार का गठन संभव हुआ।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा कि नई सरकार शांति, विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए राज्य को आगे ले जाएगी।प्रधानमंत्री ने खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी|

चुनाव आयोग का तगड़ा झटका बंगाल सरकार को — विवाद SIR मतदाता सूची पर गरमा गया राजनीति

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच जारी विवाद नया मोड़ ले चुका है, जिससे बंगाल सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। मुख्य विवाद का केंद्र है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे बदलाव और उससे जुड़ी प्रक्रियाएँ।चुनाव आयोग ने हाल ही में 25 IAS/IPS अधिकारियों को दिल्ली ब्रीफिंग में शामिल होने को कहा, जिससे राज्य प्रशासन में फेरबदल और मतदाता सूची प्रक्रिया पर नियंत्रण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। यह कदम बंगाल सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर दबाव बढ़ाने जैसा माना जा रहा है।

क्या है SIR विवाद?

चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में संशोधन किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नाम हटाए और सत्यापन शुरू हुआ है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे मतदाता अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वत: याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है।सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, और अगले सुनवाई सत्र की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही है।ममता बनर्जी ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि मतदाता सूची

अपडेट की प्रक्रिया में पक्षपात और भारी हस्तक्षेप है, और बंगाल के मतदाताओं को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उनका तर्क है कि SIR उलझनों और गलतियों से भरा हुआ है, जिससे कई पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह विवाद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल में सियासी टकराव बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग की कार्रवाइयों पर टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों की तीखी शिकायतें हैं, जबकि आयोग अपना रुख कानून और प्रक्रिया के तहत ठीक बता रहा है।सीएम ममता बनर्जी ने SIR पर तीखा विरोध व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि ज़्यादती और पक्षपातबाज़ी से कार्य किया जा रहा है और कई ऐसे मतदाता जिनका नाम गलत तरीके से 'मृत' या 'अनमैप्ड' बताया गया है, उनका वोट छीनने की कोशिश हो रही है।इसके तहत चुनाव आयोग ने कई सीनियर IAS/IPS अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर विभिन्न ब्रीफिंग और निर्देश सत्रों में शामिल होने को कहा, जिससे बंगाल प्रशासन की उच्च स्तरीय तैयारियों पर सियासी बहस तेज हो गई है।सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर गंभीर सुनवाई जारी है, जहाँ बंगाल सरकार ने आयोग के SIR निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की है। कोर्ट ने आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है।राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा भाजपा-TMC के बीच चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बनता जा रहा है, जहाँ विपक्ष बंगाल सरकार को मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाता दिख रहा है।

सदन स्थगित-

प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले लोकसभा में हंगामा

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन को संबोधित करने से कुछ ही मिनट पहले लोकसभा स्थगित कर दी गई। यह घटनाक्रम विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध प्रदर्शन के सत्ता पक्ष के पास झड़प में तब्दील होने के बाद हुआ, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि कई विपक्षी महिला सांसद सदन के वेल में घुस गईं, प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ीं और वरिष्ठ मंत्रियों की बार-बार की गई अपील को अनसुना कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया और उनके आक्रामक व्यवहार से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही सुचारु रूप से चल पाना संभव नहीं हो सका और स्पीकर को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे पर संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने के आरोप लगाए।

भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी: जयशंकर की स्कॉट बेसेंट और मार्को रुबियो से मुलाकात

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की वर्तमान अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की वर्तमान अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई। भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

वहीं बेसेंट ने एक पोस्ट में कहा कि उन्हें जयशंकर से मुलाकात करके अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ''इस बातचीत के दौरान हमने आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के महत्व के साथ-साथ आपसी हित के अन्य राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की।'' जयशंकर दो से चार फरवरी तक अमेरिका की यात्रा पर हैं और बुधवार को विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से बुलाई गई महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में वह हिस्सा लेंगे। जयशंकर ने विदेश मंत्रालय में रुबियो के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की जहां दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति का ''स्वागत'' किया और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं खनन पर द्विपक्षीय सहयोग को ''औपचारिक रूप देने'' पर भी चर्चा की। जयशंकर की बेसेंट और रुबियो के साथ बैठक ट्रंप द्वारा 'ट्रुथ सोशल' पर यह घोषणा करने के एक दिन बाद हुई कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। जयशंकर ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

मध्य प्रदेश में करंट से बाघ और बाघिन की मौत, 7 आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के उत्तर वन मंडल में एक बाघ और एक बाघिन की करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो किसानों सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों बाघ-बाघिन सोमवार को मृत मिले थे। इस साल मध्य प्रदेश में बाघों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। इन दो मौतों के साथ ही राज्य में इस साल अब तक 9 बाघों की जान जा चुकी है, जो संरक्षण प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शहडोल उत्तर संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) तरुणा वर्मा ने फोन पर पीटीआई-को बताया, ''आरोपियों ने मुख्य रूप से जंगली सूअरों को पकड़ने के लिए कथित तौर पर बिजली के जाल बिछाए थे।'' उन्होंने कहा कि हालांकि, करीब छह साल की एक बाघ और करीब सात साल की बाघिन खेतों में बिछाए गए जाल में फंस गई और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि दोनों बाघों की मौत का कारण करंट लगना ही था।

2045 तक भारत में कैंसर मरीजों की संख्या 67% बढ़ सकती है बता रहे एक्सपर्ट

भारत अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ट्रेड डील की दिशा में, पीएम मोदी ने संभाली कमान; 7-8 फरवरी अहम साबित हो सकते हैं

यूरोपीय संघ के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील पर सहमति बन गई है. इन दोनों ट्रेड डील्स को मदर ऑफ ऑल डील और फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है. इस बीच इन दोनों से इतर भारत एक और बड़ी ट्रेड डील की ओर बढ़ रहा है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 और 8 तारीख को मलेशिया के दौरे पर जाएंगे. यह दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' को नई गति देने वाला होगा, जहां व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी. सूत्रों के अनुसार, इस दौरे के एजेंडे में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ASEAN-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा शामिल है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में दो बड़ी ट्रेड डील की है. जनवरी के अंत में भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर समझौता किया, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है.

इस डील से EU में भारतीय निर्यात पर 99 फीसदी से अधिक टैरिफ खत्म या कम होंगे, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में इसके बाद सोमवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सहमति हो गई. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया. यह डील रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव के बाद हुई है. यह समझौता भारतीय निर्यातकों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत देगा और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत करेगा

बीच समुद्र में बड़ी कार्रवाई: US ने मार गिराया ईरानी ड्रोन, खामनेई की धमकी से हड़कंप

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार (6 फरवरी) को दोनों पक्षों के अधिकारियों की ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर बैठक होने की उम्मीद है, इसी बीच तेहरान ने अरब सागर से गुजर रहे एक अमेरिकी विमानवाहक पोत की ओर ड्रोन भेजा। जवाब में अमेरिकी सेना ने उसे मार गिराया। अमेरिकी सेना के अनुसार, 3 फरवरी को ईरान के शाहेद-130 ड्रोन ने अरब सागर से गुजर रहे यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की ओर आक्रामक रूप से हमला किया। यह पोत ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर था। इसके जवाब में अमेरिकी युद्धपोत ने एफ-35सी लड़ाकू विमान से ड्रोन को मार गिराया। ईरानी ड्रोन की यह गतिविधि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नाराज कर सकती है, जो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम यूएसएस अब्राहम लिंकन की सैन्य शक्ति को दर्शाता है, जिसे अमेरिकी नौसेना दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत बताती है। मंगलवार को घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जब वह मानवरहित विमान यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की ओर आक्रामक रूप से बढ़ रहा था। यह पोत अरब सागर में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर स्थित था। हॉकिन्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना द्वारा तनाव कम करने के उपाय किए जाने के बावजूद, ईरानी ड्रोन पोत की ओर बढ़ता रहा।" उन्होंने आगे बताया कि लिंकन के एक एफ-35सी लड़ाकू विमान ने पोत और उसके कर्मियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन को मार गिराया।

जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में जैश की साजिश नाकाम, गुफा में छिपे दो पाकिस्तानी आतंकी ढेर

बुधवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा मजालता इलाके के चारों ओर घेरा कड़ा करने के दौरान दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। उनकी पहचान जब्बार और मावी के रूप में हुई है। घटनास्थल से भारी गोलीबारी की सूचना मिली है और अभियान अभी भी जारी है। उनके ठिकाने की सूचना मिलने के बाद, सुरक्षा बलों ने भागने के सभी रास्ते बंद करने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए पाए गए, जिसके बाद तुरंत और भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों के सटीक ठिकाने का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। उनकी स्थिति की पुष्टि होते ही, सुरक्षा कर्मियों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर दिया। मंगलवार शाम को आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिसके चलते गोलीबारी और विस्फोटों का एक नया दौर शुरू हो गया। इसके बाद पैराट्रूपर्स और डॉग स्क्वाड समेत अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घेराबंदी और कड़ी करने के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से दोनों आतंकवादियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया। उनकी लोकेशन की पुष्टि होते ही सुरक्षाकर्मियों ने रॉकेट लॉन्चर से उन्हें खत्म कर दिया। आतंकवादियों के ठिकाने की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने भागने के सभी रास्ते बंद करने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए पाए गए, जिसके बाद तुरंत ही भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने गुफा को खाली कराने और आगे किसी भी तरह के खतरे को रोकने के लिए पूरी सावधानी और सटीकता से अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों से एक एम4 कार्बाइन और एक एके-47 राइफल बरामद की, जो इस अभियान की अहमियत को दर्शाती है। हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी आतंकवादी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है, और सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि इलाके में आगे कोई भी खतरा न रहे।

संपादक की कलम से

विकास एक ऐसा व्यापक शब्द है, जो केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और पर्यावरण सहित जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। किसी राष्ट्र की प्रगति को सही मायनों में मापने के लिए केवल जीडीपी या औद्योगिक उत्पादन को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, सामाजिक संरचना और समान अवसरों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है।विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आर्थिक विकास। जब किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लोग अपने जीवन स्तर को सुधार पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, औद्योगिक निवेश, नई तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति आर्थिक विकास को तेज करती हैं। लेकिन केवल आर्थिक वृद्धि से ही विकास पूरा नहीं होता। आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए सामाजिक विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण और दलित-पिछड़े वर्गों के लिए समान अवसर समाज के संतुलित विकास में योगदान देते हैं।विकास का तीसरा आयाम है अंतरसंस्कृतिक और नैतिक विकास। किसी भी समाज की प्रगति तभी स्थायी होती है जब उसके नागरिकों में सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य और सहयोग की भावना विकसित हो। केवल भौतिक विकास से समाज में असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।आज का विकास तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के बिना अधूरा है। इंटरनेट, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट शहर, और आधुनिक कृषि पद्धतियाँ समाज और राष्ट्र को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को अवसर देते हैं और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही, विज्ञान और तकनीक स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार लाती है।पर्यावरणीय संतुलन और स्थायी विकास भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विकास केवल उद्योग, निर्माण और शहरों तक सीमित रहेगा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं होगी, तो यह अस्थायी और हानिकारक साबित होगा। सतत विकास के लिए हर कदम पर ऊर्जा की बचत, हरित तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है।अंत में, विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास और सहयोग से ही संभव है। केवल सरकार की नीतियाँ ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी, समाज की जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है। जब आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, तभी विकास का वास्तविक अर्थ पूरा होगा।विकास केवल आधुनिक इमारतों या बड़े उद्योगों का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज में सुधार, जीवन की गुणवत्ता, समान अवसर और संतुलित पर्यावरण के साथ एक स्थायी और समग्र प्रगति का नाम है। इसी को अपनाकर हम एक मजबूत, सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

नए अवतार में ममता: सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी CM ने बहस की, जज भी ध्यान से सुनते रहे

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद अपनी बात रखी और चुनाव आयोग पर वोटर सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत में एक अलग ही रूप में उपस्थित हुईं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने ममता बनर्जी से कहा, "आपने बहुत अच्छा वकील चुना है, आप उन्हें बहस करने दें।" इस पर ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, "सेव डैमोक्रेसी।" यह पल दर्शाता है कि ममता न केवल एक राजनेता के रूप में, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और न्याय की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थीं।सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह घटना अनूठी थी क्योंकि किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने स्वयं अदालत में बैठकर बहस की। ममता बनर्जी ने वकीलों के साथ बैठकर बंगाल के SIR (Special Identification Registration) मुद्दे पर दलीलें दीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और संबंधित अधिकारियों ने उनके सवालों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी कुछ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की थी। ममता बनर्जी के मामले में यह पहली बार था कि किसी मुख्यमंत्री ने सीधे बहस में भाग लिया।सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी वकीलों की कतार में सबसे आगे बैठी हुई नजर आईं। उन्होंने कहा, "मैं भी इसी राज्य से हूं, इसलिए मैं इसे विस्तार से समझा सकती हूं।" उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि न्याय मिलने में विलंब के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे सामान्य परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी पार्टी और राज्य के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनके इस आत्मीय और संवेदनशील भाषण ने अदालत के वातावरण को भी प्रभावित किया।मुख्य न्यायाधीश ने ममता बनर्जी को आश्वासन देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मामले में पक्षकार है और केस लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ देश के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं, जैसे कपिल सिब्बल और गोपाल, जो बहस कर रहे हैं। इस पर ममता ने कहा कि जब वकील शुरू से लड़ रहे हैं, रिकॉर्ड पर बार-बार दलीलें दी जा रही हैं, छह बार चुनाव आयोग को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला, तो यह स्वाभाविक है कि न्याय मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय के रास्ते पर अड़चनें महसूस हो रही हैं।ममता ने न्यायालय से आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें पांच मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। CJI ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे 15 मिनट देंगे, लेकिन पहले अदालत की ओर से कुछ बातों को समझना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर समस्या का समाधान संभव है और इस मामले का भी हल निकाला जाएगा। उन्होंने ममता को यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और उनकी पार्टी की ओर से उठाई गई सभी समस्याएं रिकॉर्ड पर हैं और उन्हें स्वीकार किया गया है।ममता ने अदालत को यह भी बताया कि वे कुछ दस्तावेज और तस्वीरें प्रस्तुत करना चाहती हैं, जो समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के सभी प्रमुख अखबारों में इन मुद्दों को प्रकाशित किया गया है और वे चाहती हैं कि इन समस्याओं का त्वरित समाधान निकले। ममता ने जोर देकर कहा कि वे अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी।उन्होंने विशेष रूप से भाषा और नामों की वर्तनी में अंतर के कारण मतदाता सूची से लोगों को बाहर किए जाने की समस्या को उठाया। ममता ने कहा कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपने आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण कई BLO (Booth Level Officers) की मृत्यु भी हो चुकी है। ममता ने इस मुद्दे को बंगाल के खिलाफ अन्यायपूर्ण लक्ष्यकरण के रूप में प्रस्तुत किया और सवाल उठाया कि यह कार्रवाई केवल बंगाल पर क्यों हो रही है, जबकि अन्य राज्यों जैसे असम में ऐसा नहीं किया जा रहा।इस पूरे घटनाक्रम में ममता ने न्यायालय को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा वास्तविक और गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास से पीछे नहीं हटेंगी। CJI ने जवाब दिया कि आधार के मुद्दे पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित समय पर समाधान निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।इस पूरी सुनवाई ने न केवल ममता बनर्जी की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि लोकतंत्र में राज्य और केंद्र के बीच संवाद और न्याय प्रणाली में जनता की आवाज कितनी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी का यह कदम इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुख्यमंत्री द्वारा सीधे बहस करना अब तक अनोखा था। उनकी दलीलों में राज्य की जनता के अधिकार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की स्पष्ट झलक देखने को मिली।इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की उपस्थिति और उनके द्वारा की गई बहस ने यह संदेश दिया कि न्याय की मांग में कोई भी व्यक्ति चाहे वह सामान्य नागरिक हो या उच्च पदस्थ मुख्यमंत्री, अपनी आवाज उठा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। इस सुनवाई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि न्यायपालिका में व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिबद्धता कैसे न्याय की दिशा में सार्थक भूमिका निभा सकती है।

India-US ट्रेड डील से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा, पीयूष गोयल ने संसद में बताए देशहित के फायदे

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को संसद सदस्यों को आश्वासन दिया कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चिंता जताई है कि भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क घटाकर शून्य कर सकता है और अमेरिका से 500 अरब अमेरिकी डॉलर के ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीद सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारत-अमेरिका संबंधों में हुई ये नई प्रगति अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। उनके कुशल नेतृत्व में भारत में युवाओं के लिए नित नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भारत और अमेरिका, यानी दुनिया के दो सशक्त लोकतंत्रों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का प्रभाव बहुत ही सकारात्मक और दूरगामी होने वाला है। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को नई गति देने का माध्यम बनेगा। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी नई ऊर्जा मिलेगी। कृषि क्षेत्र को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में, पीयूष गोयल ने लोकसभा को बताया कि दोनों देशों ने एक साल तक विचार-विमर्श किया और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांधी ने आरोप लगाया कि उस समय शीर्ष नेतृत्व का 'स्थायी आदेश' यह था कि भारतीय सेना को स्पष्ट अनुमति के बिना गोली नहीं चलानी चाहिए, भले ही चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुस आए। उन्होंने कहा कि शीर्ष का स्थायी आदेश यह था कि अगर चीनी सेना आती है, तो हमें बिना अनुमति के उन पर गोली नहीं चलानी चाहिए। नरवणे जी और हमारी सेना उन टैंकों पर गोली चलाना चाहते थे क्योंकि वे हमारे क्षेत्र में घुस आए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद से दोनों देश एक संतुलित और लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक साल में दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने कई स्तरों पर बातचीत की है। यह स्पष्ट है कि अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए दोनों देश संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं। भारत कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने में सफल रहा है। अमेरिका के भी कुछ संवेदनशील क्षेत्र थे। एक साल की बातचीत के बाद दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने व्यापार समझौते को सुनिश्चित किया।

किरन रिजिजू का राहुल गांधी को जवाब:

मनमाने नहीं, नियमों के अनुसार बोलना होगा

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलते समय संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गांधी के पत्र का जवाब दे दिया है और संसद में कोई भी सदस्य मनमाने ढंग से नहीं बोल सकता। एक दिन पहले, राहुल गांधी ने अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बोलने से रोके जाने पर चिंता व्यक्त की थी। पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि मैंने इसका जवाब दे दिया है। हम भी इंतजार करते-करते थक गए हैं, लेकिन वह बोलते नहीं हैं। उनका कहना है कि वह नियमों का उल्लंघन करके बोलेंगे। हमने दो दिन इंतजार किया, लेकिन दूसरों को भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। वह मनमाने ढंग से नहीं बोल सकते। यह भारत की संसद है, आपको नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। इस बीच, कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा कि संसद में बोलने का अधिकार विपक्ष के नेता और हर सांसद को है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर राहुल गांधी को जानबूझकर रोकने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और हर सांसद को बोलने का अधिकार है। मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी भाजपा सरकार उन्हें रोकने पर तुली हुई है... भाजपा का इतिहास इसी तरह लिखा गया है। अतीत में, उन्होंने सांसदों को निलंबित करके सदन चलाया है। अगर वे विपक्ष-विहीन सदन चलाना चाहते हैं, तो चलाएं। अगर वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुधवार को लोकसभा को विपक्षी सदस्यों द्वारा बजट सत्र के दौरान एक दिन पहले आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में जोरदार नारेबाजी के बीच स्थगित कर दिया गया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर मीडिया से बात करते हुए गांधी ने भी यही आरोप लगाए थे। निलंबित सांसदों में कांग्रेस सदस्य हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यदाओराव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और डीन कुरियाकोस के साथ-साथ सीपीआई (एम) सांसद एस वेंकटेशन भी शामिल हैं।

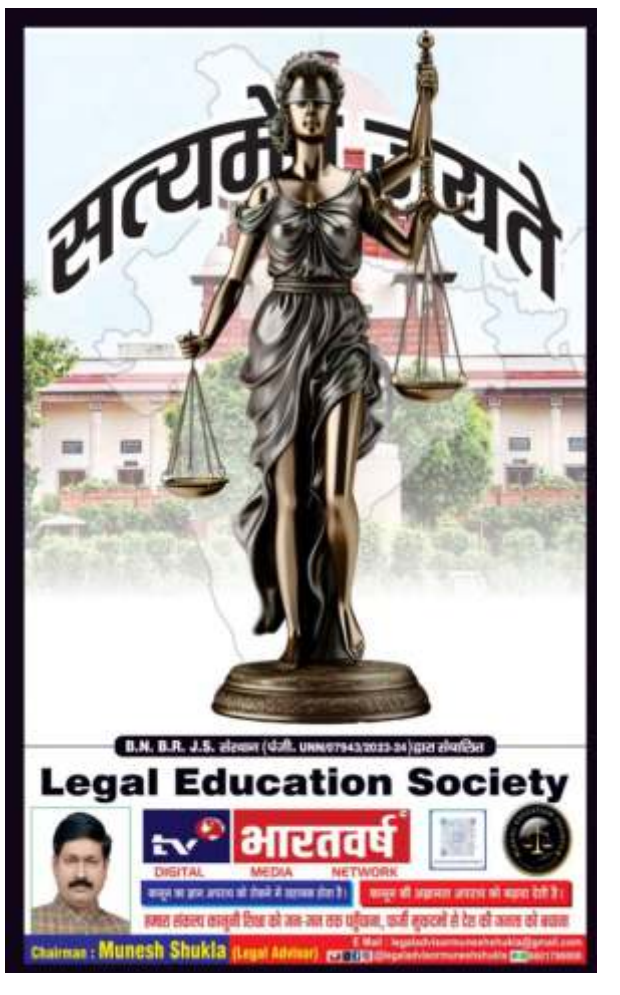

जेईई मेन 2026 सेशन-1:

NTA ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की, आपत्ति दर्ज करने का मौका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के पहले सत्र (Session 1) की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों कैंडिडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही एनटीए ने कैंडिडेंट्स की रिस्पॉन्स शीट भी प्रोवाइड कराई है। बता दें कि, इस बार जेईई मेन सेशन-1 के लिए कुल 13,50,969 कैंडिडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यदि किसी परीक्षार्थी को आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर पर डाउट या आपत्ति है, तो वह अपना ऑब्जेक्शन 5 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 5 फरवरी, 2026 तय की गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि, प्रत्येक सवाल के हिसाब से 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सभी चैलेंज की जांच करेंगे और उसके आधार पर फाइनल आंसर की जारी होगी। इसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार जेईई मेन सेशन-1 के लिए कुल 13,00,368 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। सेशन-1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आयोजित की गई थीं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई की कुल 62,500 से ज्यादा सीटों के लिए यह मुकाबला हो रहा है। एनटीए ने अप्रैल सत्र (Session 2) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने जनवरी सेशन में हिस्सा नहीं लिया या जो अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, वे 25 फरवरी, 2026 की रात 9 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। सेशन-2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। जेईई मेन के दोनों सेशन के रिजल्ट आने के बाद, कैंडिडेंट्स के स्कोर के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। टॉप 2,50,000 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके जरिए आईआईटी में दाखिला मिलता है। आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड भी वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं, जिसके 12वीं में कम से कम 75 फीसदी मार्क्स होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे समय सीमा के भीतर अपनी आंसर-की का मिलान कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए ओएमआर शीट की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in चेक करते रहें।

1 अक्टूबर से लागू होंगे क्रिकेट के 73 नियम बदले

क्रिकेट के 73 नियम बदल दिए हैं। इनमें टेस्ट मैच में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर पूरा ओवर खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच, विकेटकीपर की पोजीशन जैसे कई नियम बदले गए हैं। लेमिनेटेड बैट को सशर्त मंजूरी दी गई है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में यह सबसे बड़ा अपडेट है। क्रिकेट नियम बनाने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि टेस्ट मैचों में दिन का आखिरी ओवर अब हर हाल में पूरा कराया जाएगा। ऐसा न होने से 'खेल का रोमांच कम हो जाता है।' MCC ने कहा, 'यह अनुचित माना गया कि अगर दिन के अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रही टीम विकेट लेती है, तो बल्लेबाजी टीम को नया बल्लेबाज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती।' वहीं यह भी बयान में कहा गया कि, 'इससे समय की बचत भी नहीं होती, क्योंकि बची हुई गेंदें अगले दिन पूरी करनी ही पड़ती हैं। साथ ही इससे खेल का रोमांच कम हो जाता है। नया बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों से बच जाता है। क्योंकि आमतौर पर उस समय गेंदबाजों के लिए हालात अनुकूल होते हैं। नए नियम के तहत अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो अंतिम पूरा किया जाएगा, भले ही उस दौरान विकेट गिर जाए।'

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप:

भारत ने फाइनल में जगह बनाई

कपिल देव का पाकिस्तान पर हमला: अपने खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी, भारत से मैच का बहिष्कार गलत

भारत के महान कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के पाकिस्तान के फैसले पर सख्त एतराज जताया है। उनका कहना है कि यह फैसला किसी और को नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कपिल देव के मुताबिक, ऐसे बोर्ड-स्तरीय फैसलों की कीमत खिलाड़ियों को लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। कपिल देव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर यह फैसला खिलाड़ियों ने नहीं, बल्कि बोर्ड ने लिया है, तो इसका असर बेहद नकारात्मक होगा। उन्होंने कहा, 'अगर यह फैसला खिलाड़ियों ने लिया होता, तो वे खुद सामने आकर कहते। लेकिन जब बोर्ड तय करता है कि आप नहीं खेलेंगे, तो देश की साख गिरती है। यह पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं दिखता।' कपिल देव ने इस फैसले को पाकिस्तान के युवा क्रिकेटरों के लिए घातक बताया। उनके मुताबिक, विश्व कप जैसे मंच पर खेलने का मौका हर खिलाड़ी का सपना होता है, और उसे छीन लेना एक पूरी पीढ़ी के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा, 'आप एक

पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वर्षों से शानदार टैलेंट दिया है, लेकिन अगर आप इन लड़कों को विश्व कप खेलने नहीं देंगे, तो आप खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने ही खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।' पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगा, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप स्टेज मैच में नहीं उतरेगा। यह फैसला आईसीसी द्वारा बांग्लादेश की मैच स्थान बदलने की मांग खारिज किए जाने के बाद सामने आया, जिसके बाद टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की एंट्री हुई।

टी20 विश्वकप 2026: चैंपियन धोनी ने टीम इंडिया की जीत पर रखी राय, दी सावधानी बरतने की सलाह

भारत को 2007 में टी20 विश्व कप के पहले संस्करण में ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भरोसा है कि टीम इंडिया आगामी टी20 विश्व कप में अपने खिताब के बचाव में सफल रहेगी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जतिन सप्रू के साथ बातचीत करते हुए धोनी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट की सबसे कम्प्लीट और शक्तिशाली टीम है। उनके मुताबिक, भारत के पास खिताब बचाने के लिए हर जरूरी संसाधन मौजूद है। धोनी ने टीम की ताकत पर बात करते हुए कहा, 'टीम इंडिया टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। एक अच्छी टीम के लिए जो कुछ चाहिए, वह सब इस टीम के पास मौजूद है।' धोनी का मानना है कि खिलाड़ियों का अनुभव और उनकी भूमिका की स्पष्टता इस भारतीय टीम को बाकी टीमों से अलग बनाता है। टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में कई मौकों पर दबाव की स्थिति बनती है और बार-बार मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अनुभवी खिलाड़ी ही टीम को संभाल पाते हैं। उन्होंने कहा, 'इस टीम के पास अनुभव है। खासकर इस फॉर्मेट में खिलाड़ियों ने लंबे समय तक दबाव में खेला है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छे से जानता है और पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है। जहां एक ओर धोनी ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया, वहीं उन्होंने एक अहम चेतावनी भी दी। उनके मुताबिक, ओस (ड्यू) ऐसा फैक्टर है जो किसी भी मैच का रुख पलट सकता है। धोनी ने साफ कहा, 'जो चीज मुझे परेशान करती है, वह है ओस। मुझे ओस बिल्कुल पसंद नहीं है।

यह खेल में बहुत कुछ बदल देती है। मेरे खेलने के समय में भी ओस सबसे डराने वाली चीजों में से एक थी, क्योंकि फिर टॉस बेहद अहम हो जाता है।' धोनी का मानना है कि अगर परिस्थितियां संतुलित रहीं, तो भारत ज्यादातर मुकाबलों में विजेता बनकर उभरेगा। उन्होंने भरोसे के साथ कहा, 'अगर हम 10 मैच दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलें और परिस्थितियां न्यूट्रल रहें, तो भारत उसमें से ज्यादातर मैच जीतेगा। धोनी ने

आगे कहा, 'बस दिक्कत जो है, वह यह है कि आपकी टीम के किसी खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं है और सामने वाली टीम के किसी खिलाड़ी का बहुत अच्छा दिन जा रहा है। टी20 क्रिकेट में ऐसा कई बार होता है। बस यह देखने वाली बात होगी कि यह लीग स्टेज में होता है या फिर नॉकआउट स्टेज में होता है। तब हमें प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ेगी। धोनी ने कहा, 'टीम मैनेजमेंट समते हर कोई यही मनाता है कि चुनी गई टीम से कोई खिलाड़ी चोटिल न हो। जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, वो वह रोल अच्छे से निभाएं। अगर ऐसा होता है तो मैं यह कहकर नजर नहीं लगाना चाहता, लेकिन भारत सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत टीम होगी।'

आज की तस्वीर

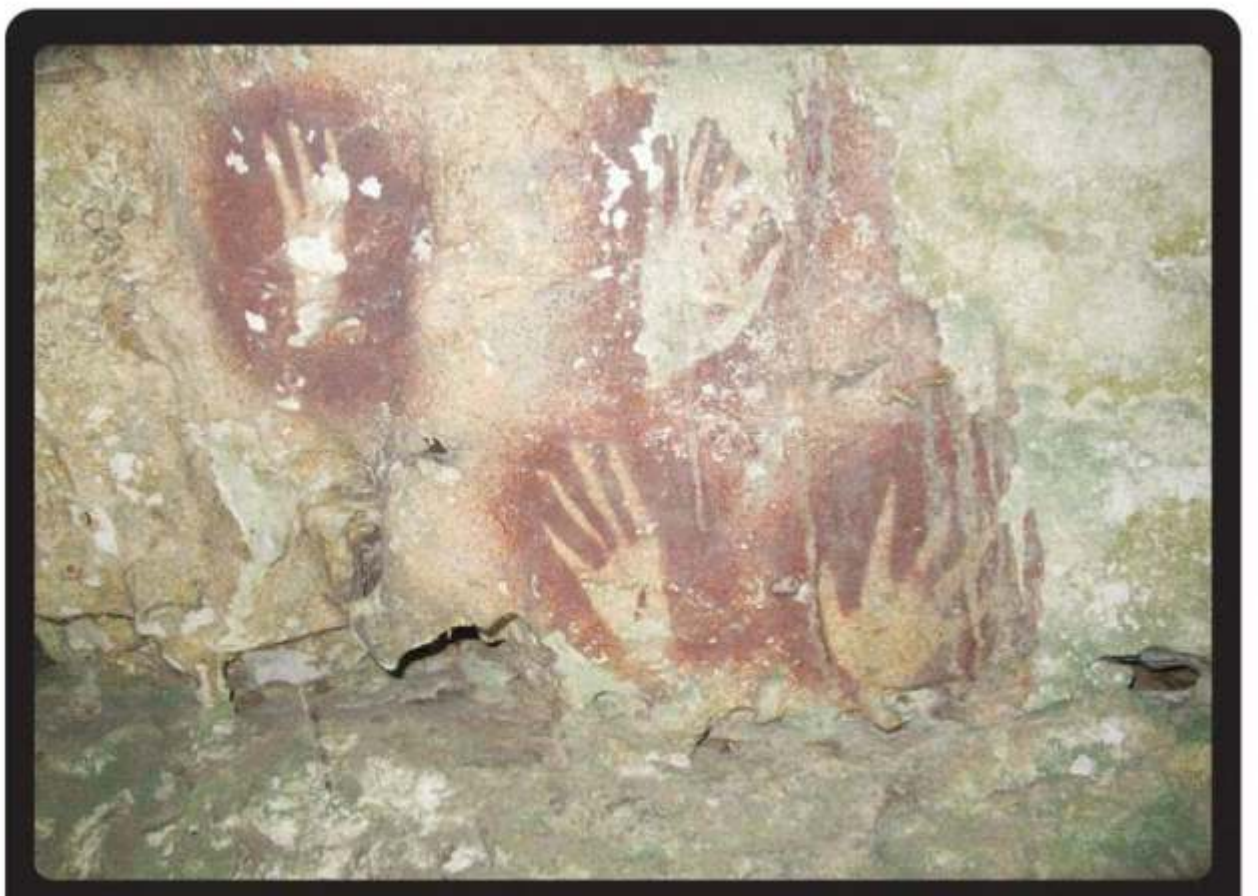

प्राचीन कला के सबूत

इंडोनेशिया की एक दूरस्थ गुफा में मिले हाथों के प्राचीन निशान मानव इतिहास की शुरुआती रचनात्मक अभिव्यक्ति माने जा रहे हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार इन शैलचित्रों की उम्र लगभग 67,800 साल है. जो अब तक ज्ञात रॉक आर्ट से भी पुरानी हो सकती है. यह खोज बताती है कि आदिम मानव बहुत पहले से ही कला और प्रतीकों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है. (Photo: AP)

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बॉयफ्रेंड के लिए लड़की ने खाए 60 तमाचे

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें किसी लड़की या लड़के के चक्कर में लड़ाई हो जाती है. पहले ऐसा सुनने में आता था कि किसी लड़की के चक्कर में लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ ये भी बदल गया है. फिलहाल एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को दो लड़कियां मिलकर थप्पड़ मार रही हैं. हालांकि, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लड़ाई लड़के की वजह से हो रही है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है और अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की दूसरे लड़की को लगातार थप्पड़ मार रही

है और वो लड़की मार खा रही है. जब लड़की कुछ थप्पड़ खा लेती है तो, वो मारने वाली लड़की को रोकती लेकिन वो नहीं रुकती है और उसे और ज्यादा मारने लगती है. कुछ देर के बाद वीडियो में दूसरी लड़की आती है, जो उसे पहली वाली से भी ज्यादा थप्पड़ मारती है. वीडियो में देखा जा रहा है कि इस दौरान मारने वाली लड़की मोबाइल में मैसेज पढ़ रही है. ⊙

आस्था के केंद्र में बोल्ड फोटोशूट

थाईलैंड में सैकड़ों साल पुराने एक प्राचीन बौद्ध मंदिर स्थल पर कुछ विदेशी टूरिस्ट योगा करते दिखाई दिए थे. इस दौरान इन्होंने बिकनी जैसे स्पोर्ट्सवियर पहन रखे थे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई. इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह जिम नहीं है. यहां ऐसे अनुचित कपड़ों में योगा करना प्रतिबंधित है. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, चियांग माई स्थित वाट फा लाट ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्राचीन स्थल पर ऐसा अपमानजनक व्यवहार जारी रहा तो वह विदेशी पर्यटकों के लिए इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. ⊙

गर्लफ्रेंड-एक्स बॉयफ्रेंड का झगड़ा थी वजह

ट्रंप के बेटे ने क्यों किया लंदन पुलिस को फोन?

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की एक दोस्त ने लंदन से उन्हें तब वीडियो कॉल किया जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर रहा था. फिर ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप ने उस महिला की जान बचाई और अमेरिका से सीधे ब्रिटेन की पुलिस को फोन घुमा दिया.

मेट्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला ने लंदन की अदालत को बताया कि बैरन ट्रम्प ने उसकी जान बचाई, जब उसकापूर्व प्रेमी बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे को महिला ने वीडियो कॉल किया था. उसमें बैरन ट्रंप ने देखा कि मात्वेई रुमियांस्तेव नाम का एक रूसी शख्स उसकी महिला मित्र की पिटाई कर रहा था. इसके बाद बैरन ट्रंप ने लंदन की पुलिस को संपर्क

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने अमेरिका से लंदन पुलिस को कॉल करके एक महिला की जान बचाई. (Photo - Instagram/@barrotrump)

किया. ऐसा दावा किया जाता है कि 22 साल का रुमियांस्तेव उस महिला का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे छोटे बेटे की दोस्त है. रूसी शख्स को यह बात बुरी लगती थी कि उसके गर्लफ्रेंड की दोस्ती ट्रंप के बेटे से है. स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में पीड़ित महिला ने ये पूरी कहानी सुनाई. उसने बताया कि कैसे बैरन ट्रंप ने 999 ऑपरेटरों से कहा कि मुझे अभी-अभी एक लड़की का फोन आया है जिसे मैं जानता हूं. उसकी पिटाई हो रही है. यह मामला पिछले साल 18 जनवरी की है. जब सुबह 2.23 बजे ब्रिटेन की पुलिस को फोन किया गया था. फोन अमेरिका से आया था और उसने महिला का पता देने के बाद दोहराया कि यह वास्तव में एक आपातकालीन स्थिति है.मुझे उसने वीडियो कॉल किया था, जिसमें एक आदमी उसे पीट रहा था. पुलिस के पहुंचने के समय का बॉडीवियर फुटेज अदालत में चलाया गया, जिसमें अधिकारी महिला से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या रुमियांस्तेव के हमले के दौरान वह स्ट्रीमिंग कर रही थी. ⊙

तापसी पन्नू की 'अस्सी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, कहानी बयां करती है इंसाफ की तलाश

डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अपनी फिल्मों के जरिए समाज के उन बातों को दिखाना पसंद करते हैं, जिन्हें लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'ASSI' भी कुछ ऐसी ही कड़वी हकीकत लेकर आ रही है. जबरदस्त मोशन पोस्टर से चर्चा बटोरने के बाद, अब मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी यह इन्वेस्टिगेटिव कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में तापसी पन्नू के लीड रोल में है. जिसे एक पावर-पैक्ड कलाकारों की टीम का साथ मिला है. तापसी के साथ, फिल्म में कानी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब हैं, और नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा भी दिखाई देंगे फिल्म का ट्रेलर एक बेहद गंभीर और सधे हुए नोट पर शुरू होता है. इसमें तापसी पन्नू एक ऐसी वकील के अवतार में हैं, जो कहती हैं, 'अपराध वाले दिन देशभर में 80 रेप कंपलेंट हुई थीं, जिनमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है.' इसके बाद दिखाया जाता है कि एक महिला को एक कार से किडनैप कर लिया जाता है. बाद में उस महिला का गैंगरेप करके उसको रेलवे पटरियों के पास छोड़ दिया जाता है. इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कार्ट रूम ड्रामा शुरू होता है. गुलशन कुमार और टी-सीरीज के प्रोडक्शन में बनी अस्सी फिल्म को डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ने किया है. यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि 'मुल्क' और 'थप्पड़' फिल्म के बाद तापसी और अनुभव की जोड़ी इस फिल्म के साथ क्या कमाल करती है.

ट्रेलर लॉन्च पर तापसी पन्नू ने कहा, 'मुझे लगा कि इन कहानियों को एक साथ लाने और लोगों के सामने रखने का समय आ गया है ताकि हम खुद को याद दिला सकें कि हम रोजाना अपराध की खबरों के तौर पर जो पढ़ते हैं, उसे कभी भी सामान्य नहीं मानना चाहिए. ये घटनाएं चिंताजनक हैं, ये हमारे आस-पास हो रही हैं, और ऐसा लगता है कि ये बढ़ रही हैं. कभी-कभी यह सिर्फ अपराध के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में भी होता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार इसे रोकने के लिए कितना कम करते हैं. जब हमने इसे दो घंटे की कहानी का रूप दिया, तो एक कलाकार के तौर पर यह मेरे लिए बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि यह आपको उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं.' ट्रेलर पर बात करते हुए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा, 'मेरे लिए, मेरी फिल्म को कहानी के मूल तक पहुंचना चाहिए. ASSI के साथ, ऐसा लगा कि यह ठीक उसी जगह पर जोर से लगी जहां इसे लगना चाहिए था. उस असर ने मुझे यह फिल्म बनाने पर मजबूर किया. कहानी रोज़ाना की खबरों और उन सच्चाइयों से ली गई है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करना चुनते हैं

अखिलेश यादव ने केंद्र की विदेश नीति पर किया निशाना:

चीन को जमीन, अमेरिका को बाजार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'समझौता' नहीं बल्कि 'डील' बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की, और अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात से 'सनातनियों' के व्रत पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को केंद्र सरकार पर अमेरिका के उस दावे को लेकर तीखा प्रहार किया, जिसमें कहा गया था कि भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर शून्य कर सकता है और अमेरिका से 500 अरब अमेरिकी डॉलर के ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और कोयला उत्पाद खरीद सकता है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'ढील' करार दिया और आरोप लगाया कि अगर अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पाद भारत में आयात किए जाते हैं, तो 'सनातनियों' को अपने व्रत रखने में कठिनाई होगी। अखिलेश ने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता 'समझौता' नहीं, बल्कि 'ढील' है। हमने अपना पूरा बाजार उन्हें सौंप दिया है। सनातनियों को सोचना होगा कि उनका व्रत 'सनातन' कैसे रहेगा। अगर डेयरी उत्पाद वहां से आते हैं, तो सनातनियों और भारतीयों का व्रत कैसे चलेगा? यह चिंता का विषय है। स्वदेशी के नारे लगाने वाले भाजपा के सहयोगी कहां हैं? देश इस समझौते के बारे में जानना चाहता है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने से देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों का समर्थन किया है और उनके हितों की रक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भारत की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर एक पत्रिका लेख का हवाला देने का बचाव करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने केंद्र से संसद में चीन के साथ संबंधों पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि चर्चाएँ न हों। हमने देखा है कि जब विपक्ष के नेता और अन्य दलों ने चीन के मुद्दे पर विस्तृत जानकारी मांगी, तो भाजपा पीछे हट गई। हम दोहराते हैं कि हमें चीन के साथ अपने संबंधों पर हमेशा विचार-विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और हमारे संबंध, विशेष रूप से चीन के साथ, समय-समय पर अच्छे और बुरे रहे हैं। हमने अपनी जमीन खो दी है। देश को यह जानना चाहिए कि सशस्त्र बलों का इस बारे में क्या कहना है। हम न केवल चीन को जमीन खो रहे हैं, बल्कि अपना बाजार भी खो रहे हैं। बाजार का एक हिस्सा पिछली सरकारों के दौरान खो गया था, और कुछ हिस्सा वर्तमान सरकार के तहत खो गया है।

लखनऊ में बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को रौंदा

लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार 40 साल के ललित चौधरी की मौत हो गई। वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल ललित को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना अमौसी औद्योगिक क्षेत्र (नादरगंज) में बद्री नगर पुलिया से आगे उस समय हुई, जब ललित चौधरी रात करीब 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर घर वापस जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ललित बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में ललित को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही ललित चौधरी की मौत हो गई। बंथरा के औरावां निवासी राममिलन के अनुसार, उनके चचेरे भाई ललित चौधरी (40) अपनी पत्नी पूजा के साथ सरोजनी नगर की जयराज पुरी कॉलोनी में रहते थे। वह अमौसी औद्योगिक क्षेत्र (नादरगंज) स्थित गोमती ब्रेड कंपनी में नौकरी करते थे। घटना के बाद कार चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैगनआर कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। राममिलन ने बताया कि ललित को आज अपने मामा के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए काकोरी के मौंदा गांव जाना था।

यूपी: अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय बढ़कर ₹17 हजार होगा

यूपी के अनुदेशक शिक्षकों को 17000 हजार रुपए मानदेय का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। साथ ही यह आदेश दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से यह पद ऑटोमैटिक तरीके से सृजित है। अनुदेशकों को 17 हजार रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। दरअसल, अनुदेशक 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मानदेय बढ़ाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में मंगलवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई हुई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की डबल बेंच ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को तीन दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट की टिप्पणियों से अनुदेशकों के पक्ष में माहौल बनता नजर आया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने कहा, "जब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है?" कोर्ट की इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों की उम्मीदें और मजबूत हो गईं। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार बृजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि यह अनुदेशकों की बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुदेशकों के साथ न्याय हुआ है। उन्हें 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बृजेश इस पूरे मामले में अनुदेशकों को विधिक सलाह देते हैं। वह मूलरूप से अमेठी के रहने वाले हैं।

लखनऊ में चली शीतलहर, अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड

लखनऊ में सुबह कोहरा छाया रहा। शीतलहर भी चली। 10 बजे के बाद हल्की धूप निकली। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री घटकर 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात में 14.3 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान नहीं गया। यह सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज (बुधवार को) अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दिनभर करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लखनऊ में मंगलवार की सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे अनुमान था कि रात में कड़ाके की ठंड रहेगी। लेकिन, दिन में चटक धूप निकलने से सुबह के बारिश और सर्द हवाओं से राहत मिल गई। इसके बाद रात में सामान्य तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने के बजाय 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

यह प्रदेश के अन्य जिलों में सबसे ज्यादा तापमान रहा। इस तरह से यह लगातार तीसरा दिन रहा जब रात का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज रात से अगले 5 दिन के लिए ठंड बढ़ने और बरकरार रहने का अनुमान जताया है।

बाइक और साइकिल टकराने पर किसान नेता की हत्या

लखनऊ में बाइक से साइकिल टच हो जाने के मामूली विवाद में किसान नेता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने शराब के नशे में ईंट और लात-घूंसों से पीट-पीटकर हत्या करने की बात कबूली है। एडीसीपी साउथ रल्ला पल्ली बसंथ कुमार ने बताया- सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के मोहन कटरा बक्कास गांव के रहने वाले सुशील और बुद्धखेड़ा गांव के रहने वाले दीपक कुमार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई हैं और हत्या करने के बाद घर में जाकर सो गए थे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के मुल्ला खेड़ा गांव के पास मंगलवार सुबह सड़क किनारे किसान नेता का शव पड़ा मिला था। मृतक की पहचान ग्राम चौरासी निवासी संतराम (40) पुत्र दुलारे रावत के रूप में हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। मृतक के भाई मस्तराम की लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

यूपी: मिलावटी पेट्रोल का धंधा पकड़ा, STF ने आरोपी को केमिकल के साथ गिरफ्तार किया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को मिलावटी पेट्रोल की अवैध सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेट्रोल में एथेनॉल/साल्वेंट केमिकल मिलाकर अपमिश्रित पेट्रोल की सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में साल्वेंट केमिकल और पेट्रोल भी बरामद किया गया है। बुधवार को एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी कानपुर-अलीगढ़ हाईवे के पास मानीमऊ, कन्नौज से की है। गिरफ्तार आरोपी राजेन्द्र पाल की पहचान कानपुर के रतनपुर, थाना पनकी के रूप में हुई है।

दरअसल, एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह पेट्रोल में अवैध रूप से एथेनॉल और साल्वेंट केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल तैयार कर रहा है जिसे कानपुर, कन्नौज, लखनऊ समेत आसपास के जिलों में सप्लाई कर रहा है। इस सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अमित कुमार नागर के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा लगातार जानकारी हासिल की जा रही थी। इस दौरान यह सामने आया कि एक गिरोह के सदस्य कानपुर-अलीगढ़ हाईवे के पास यश ढाबे के पीछे मैदान में खड़े पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल चोरी करते थे। इसके बाद उसी पेट्रोल में साल्वेंट केमिकल मिलाकर मिलावटी पेट्रोल तैयार किया जाता और फिर उसे विभिन्न जिलों में खपाया जाता था। पूछताछ में आरोपी राजेन्द्र पाल ने बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना अमित पाल निवासी कन्नौज है। गिरोह के अन्य सदस्य सौरभ यादव, धर्मराज और हंसराज पाल हैं। यह गिरोह पेट्रोल में साल्वेंट मिलाकर उसे 80 से 85 रुपये प्रति लीटर की दर से सप्लाई करता था, जबकि साल्वेंट केमिकल 30 रुपये प्रति लीटर में मंगाया जाता था। पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल निकालकर उसी मात्रा में केमिकल मिलाया जाता था, ताकि टैंकर में मात्रा का अंतर न दिखे। एसटीएफ ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।

लखनऊ DM की मदद से दिव्यांग महिला को मिली ई-स्कूटी

लखनऊ में एक दिव्यांग महिला को प्रशासन और समाजिक सहयोग के माध्यम से इलेक्ट्रिक 3-व्हील स्कूटी प्रदान की गई है। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग मिलकर जरूरतमंद नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महिला ने अपनी समस्या सीधे जिलाधिकारी लखनऊ, विशाख जी. को 29 जनवरी 2026 को जनता दर्शन के दौरान प्रार्थना पत्र सौंपकर पहुंचाई थी। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपनी मुश्किलों का विस्तृत विवरण दिया था और मदद की अपील की थी। उनके द्वारा बताई गई समस्याओं में घर से बाहर निकलने में असमर्थता, रोजमर्रा के कामों को अकेले करना और अपने छह वर्षीय बेटे को साथ लेकर आना-जाना प्रमुख रूप से शामिल था। खुशबू, जो पारा निवासी हैं, चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इसके कारण वह अपने दैनिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना असंभव पाती थीं। बच्चे की देखभाल, घर के छोटे-बड़े काम और सार्वजनिक स्थानों पर जाने जैसी गतिविधियां उनके लिए भारी चुनौती बन गई थीं। यह स्थिति उनके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में थकान और दबाव पैदा कर रही थी। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाना ही सबसे उचित रास्ता है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए।

जिलाधिकारी लखनऊ, विशाख जी. ने 29 जनवरी 2026 को जनता दर्शन के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया। उन्होंने महिला की समस्या का समाधान करने के लिए जिला दिव्यांगजन अधिकारी, शशांक सिंह को जिम्मेदारी सौंपते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। शशांक सिंह ने तुरंत कार्यवाही शुरू की और महिला की जरूरतों और मुश्किलों का आकलन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिला को केवल वाहन ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे के लिए भी उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में सबसे पहला कदम महिला के बेटे के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करना था। प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया, ताकि माता और बच्चे दोनों की रोजमर्रा की गतिविधियों में सुधार हो सके। इसके बाद महिला की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर या ई-स्कूटी की जरूरत को पूरा करने की योजना बनाई गई। हालांकि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से फिलहाल कोई शासकीय योजना इस प्रकार के ई-वाहनों की उपलब्धता के लिए संचालित नहीं थी। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि महिला को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए। CSR के जरिए ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए फंड और संसाधनों का प्रावधान होता है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिल सके। इस निर्देश के बाद आवश्यक प्रक्रिया शुरू की गई और CSR सहयोग के माध्यम से महिला को 4 फरवरी 2026 को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, लखनऊ में इलेक्ट्रिक 3-व्हील स्कूटी सौंपी गई। ई-स्कूटी मिलने के बाद महिला ने अपनी खुशी और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अब उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अब वह अपने छह वर्षीय बेटे के साथ बाहर जा पाएंगी, रोजमर्रा के कार्य आसानी से कर पाएंगी और किसी की मदद के बिना घर के काम संपन्न कर सकेंगी। ई-स्कूटी की मदद से वह अब न केवल जीवन के दैनिक कार्यों को पूरा कर पाएंगी बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेंगी। इस सहयोग से उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना बढ़ेगी। खुशबू ने उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस सहयोग ने उन्हें सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन

जीने का अवसर दिया है। अब वह अपने जीवन में बदलाव लाने और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होंगी। ई-स्कूटी मिलने से केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बढ़ी, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में भी सुधार हुआ है। यह घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार सरकारी विभाग और प्रशासनिक तंत्र मिलकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि CSR जैसी सामाजिक जिम्मेदारी की पहलें समाज के कमजोर वर्गों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस उदाहरण से यह सीख भी मिलती है कि अगर जरूरतमंद व्यक्ति अपनी समस्या सही समय पर और सही तरीके से प्रशासन तक पहुंचाता है, तो समाधान सुनिश्चित हो सकता है। खुशबू की कहानी एक प्रेरणा बन गई है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि इच्छाशक्ति और प्रशासनिक समर्थन हो तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रशासन न केवल कानूनी मामलों और बड़े प्रोजेक्ट्स में बल्कि ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक मामलों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ई-स्कूटी मिलने के बाद खुशबू अब अपने बच्चे को साथ लेकर घर के बाहर जा सकती हैं, रोजमर्रा की खरीदारी और जरूरी कामों में आसानी महसूस करेंगी। इससे उनके जीवन में सम्मान और गरिमा की अनुभूति बढ़ी है। इसके अलावा, यह कदम समाज के अन्य दिव्यांगजनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। प्रशासन की यह पहल यह दिखाती है कि अगर सरकार और संबंधित विभाग सक्रिय हों, तो हर नागरिक, चाहे वह किसी भी शारीरिक या मानसिक चुनौती से गुजर रहा हो, उसे मदद मिल सकती है।

पुरानी रंजिश में महिला और बेटे पर हमला

उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र स्थित मंशाखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर हमला किया गया। इस मारपीट में महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता की शिकायत पर गंगाघाट पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंशाखेड़ा निवासी दीदी पत्नी मैकू ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर पर मौजूद थीं। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मन्टानी, रोहित, छोटू (पुत्रगण गयाप्रसाद) और गया (पुत्र हरिलाल) पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करने लगे।

जब दीदी ने इसका विरोध किया और उन्हें गाली देने से मना किया, तो आरोपी आक्रोशित हो गए। आरोप है कि इसके बाद चारों आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों से दीदी पर हमला कर दिया। शोर सुनकर दीदी को बचाने के लिए उनका बेटा जीतू मौके पर पहुंचा। आरोपियों ने जीतू के साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस हमले में दीदी और जीतू दोनों को गंभीर चोटें आईं। मारपीट के दौरान आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि मारपीट के बाद वह मौके पर ही बेहोश हो गई थीं, जिन्हें परिजनों और ग्रामीणों की मदद से होश में लाया गया। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला व उनके बेटे को उपचार के लिए भेजा। पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

कानपुर: शिक्षकों की बर्बरता, 10 छात्र-छात्राओं को बेल्ट और डंडे से पीटा

मंधाना में जीटी रोड पर महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां प्रोफेशनल्स कोर्सेस की पढ़ाई होती है। कॉलेज में क्लासेज सुबह 9 बजे से शुरू होती है। बीबीए, बीसीए और बीटेक के कई छात्र बुधवार सुबह 9 बजे के बाद कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि देर से पहुंचने वाले छात्रों को कॉलेज में टीचरों ने पीटा। टीचरों ने कॉलेज का गेट बंद करा दिया था। इसके बाद डंटों और बेल्ट से पीटा। पिटाई से छात्र अभिषेक, चित्रांश, कृष्णा, अग्रिम द्विवेदी, अक्षांश, अस्मित सोनकर के अलावा छात्राएं मुस्कान, अंजली, अंशिका, अनन्या भी घायल हो गईं। डंडे की पिटाई से मुस्कान का हाथ फट गया। हाथ में गंभीर चोट लगने पर इन चारों छात्राओं को कॉलेज के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह बात जब कॉलेज के अंदर छात्रों को मिली तो वे भड़क उठे। छात्रों का कहना है कि सुबह शहर में घना कोहरा था। सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कॉलेज पहुंचने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित है। कुछ छात्र कोहरे की वजह कर देर से पहुंचे थे। देरी से पहुंचे छात्रों की पिटाई के बाद शिक्षकों ने दूसरे गेट को बंद कर दिया। इससे जो छात्र और बाद में आए वह बाहर ही रुक गए। उन्होंने एंट्री देने के लिए कहा तो मना कर दिया गया। इससे वहां टीचर और छात्रा के बीच बहस हो गई। आरोप है कि गुस्साए कुछ टीचर अंदर से डंडा लेकर पहुंचे और गेट पर खड़े छात्रों को पीटने लगे। इसकी जानकारी कॉलेज के अंदर क्लास में मौजूद दूसरे छात्रों तक पहुंची तो वह भड़क गए। क्लास से बाहर आकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विरोध और हंगामा बढ़ने लगा। छात्रों का हंगामा बढ़ते देख बिठूर थाने को जानकारी दी गई। पुलिस से छात्रों ने बताया कि देर से पहुंचने पर उन्हें गेट पर रोका गया और फिर लात-घूसों से पीटा। जब उन्होंने पिटाई का विरोध किया, तो टीचर ने डंडे से मारना शुरू कर दिया। छात्रों का हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र मौर्य, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल कुमार पाठक को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई है।

इसके अलावा बुधवार की कक्षाओं को भी सस्पेंड करते हुए छात्र-छात्राओं से सुरक्षित कैंपस से बाहर जाने के लिए कहा गया है। सस्पेंड किए गए दोनों टीचर के अलावा चार और टीचर प्रशांत मिश्रा और शुभम गोयनका, रोहित वर्मा, शिवानी कपूर को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर गई है। कॉलेज में कारीब 7 घंटे बवाल चलता रहा। डीसीपी, एडसीपी और एसीपी भी मौके पर डटे रहे। छात्रों का आरोप है कि वह आज 10 मिनट लेट आए थे। इस पर टीचर अनिल पाठक सहित अन्य टीचरों ने गाली देते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि टीचर लेट आने पर छात्रों से 300 रूपए लेट चार्ज लेते हैं। कॉलेज में अवैध रूप से वसूली होती है। लेट फीस न देने पर कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। छात्रों ने कहा कि अगर आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़क पर भी उतरेंगे। एसीपी कल्याणपुर के पास एक दर्जन से अधिक शिकायत दी गई हैं। पीड़ित छात्र अक्षांश अवस्थी के पिता धर्मेंद्र अवस्थी ने बिठूर में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि मेरा बेटा अक्षांश अवस्थी महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र है। मैंने बेटे को 9:00 बजे गेट पर छोड़ा था। मेरा बेटा शुक्रवार से बीमार है। टीचर अनिल पाठक, सुभाष मौर्य और पंकज ने गेट बंदकर मेरे बेटे और अन्य छात्रों को डंडे और बेल्टों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने टीचर अनिल पाठक, सुभाष मौर्य और पंकज केस दर्ज कर लिया है। बिठूर थाना प्रभारी अशोक सरोज ने बताया- छात्रों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिटाई से नाराज होकर छात्र हंगामा कर रहे हैं। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

काशी में सुपारी किलर बनारसी यादव पुलिस एनकाउंटर में ढेर

वाराणसी में सुपारी लेकर रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या करवाने वाला कुख्यात अपराधी बनारसी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह मुठभेड़ मंगलवार देर रात हुई, जब एसटीएफ को उसके ठिकाने को लेकर पुख्ता इनपुट मिला। सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने चौबेपुर रोड इलाके में घेराबंदी की और बनारसी यादव को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। हालांकि, उसने पुलिस की बात मानने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश की गोलियों से दो सिपाही बाल-बाल बच गए। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाल लिया।

एनकाउंटर के दौरान पुलिस और बनारसी यादव के बीच आमने-सामने करीब पांच राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एसटीएफ की गोलियां बनारसी को लगीं, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर स्थल से बनारसी के पास से दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। यह पूरी कार्रवाई चौबेपुर रोड पर हुई, जहां उसने भागने और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी। मारा गया अपराधी बनारसी यादव गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वह पूर्वांचल के सबसे बड़े और शातिर सुपारी किलरों में गिना जाता था। उसके खिलाफ वाराणसी, गाजीपुर समेत कई जिलों में कुल 21 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 10 हत्याओं के मामले शामिल थे। कोलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के मामले में पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। दरअसल, करीब पांच महीने पहले गाजीपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र ने 50 करोड़ रुपये की जमीन के विवाद में कोलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए योगेंद्र ने बनारसी यादव को पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। इसके बाद बनारसी ने फौजी अरविंद यादव और विशाल समेत तीन शूटरों को हायर किया। 21 अगस्त 2025 को बदमाशों ने ऑफिस जा रहे कोलोनाइजर महेंद्र गौतम को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस बनारसी यादव की तलाश में जुटी हुई थी। बनारसी यादव की खास बात यह थी कि पुलिस उसे नाम से तो जानती थी, लेकिन उसका चेहरा और तस्वीर लंबे समय तक किसी के पास नहीं थी। यही वजह रही कि वह कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बावजूद पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। वह कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता था। इसके अलावा, वह अपना हुलिया बदलने में भी माहिर था, जिससे उसे पहचान पाना और भी मुश्किल हो जाता था। सारनाथ में कोलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के बाद जब जांच आगे बढ़ी, तब बनारसी यादव का नाम खुलकर सामने आया। इसके बाद पुलिस को उसकी मौजूदगी को लेकर कुछ ठोस सुराग मिले। लंबी छानबीन और तकनीकी जांच के बाद आखिरकार पुलिस को उसकी तस्वीर हासिल हुई। तभी से एसटीएफ और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थीं। मंगलवार देर रात मिली सूचना ने पुलिस को बड़ी सफलता दिला दी। एसटीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते बनारसी यादव को घेर लिया गया। हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई और उसका अंत हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बनारसी यादव के मारे जाने से पूर्वांचल में सुपारी लेकर होने वाली हत्याओं पर बड़ा अंकुश लगेगा और कई संगीन मामलों की कड़ियां भी जुड़ सकेंगी। इस एनकाउंटर को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि बनारसी यादव लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था और उसकी तलाश में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी।

उन्नाव में गंगाघाट नगर पालिका के कार्यों पर शिकंजा, डीएम गौरांग राठी के आदेश पर शिकायतों की जांच शुरू

उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर बुधवार को गंगाघाट नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे कार्यों की शिकायतों की जांच शुरू की गई। एसडीएम न्यायिक रामदेव निषाद और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से गंगाघाट पहुंचकर मौके पर निरीक्षण किया। एसडीएम न्यायिक रामदेव निषाद ने बताया कि नगर पालिका गंगाघाट से संबंधित कई शिकायतें मिली थीं। इनमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती से जुड़ी आपत्तियां शामिल हैं। इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक अलग टीम गठित की जाएगी। यह टीम पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने थाने गेट से लेकर सेल्फी प्वाइंट तक तीन अलग-अलग स्थानों पर इंटरलॉकिंग सड़क को खुदवाकर गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मोटाई और मानकों का अवलोकन किया। यह इंटरलॉकिंग कार्य 110 मीटर लंबाई में 11.73 लाख रुपये की लागत से कराया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां साफ-सफाई, रखरखाव और संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की पड़ताल की। संबंधित कर्मचारियों से जानकारी लेकर आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम न्यायिक रामदेव निषाद ने बताया कि मौके पर की गई जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता राजेंद्र गुप्ता और राजीव शुक्ला भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने अपनी शिकायतों से जुड़े बिंदुओं को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा भी निरीक्षण के समय उपस्थित रहे और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

दिल दहला देने वाली घटना: गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की मौत, सुसाइड नोट बरामद

"मम्मी, पापा, सॉरी" — ये वे आखिरी शब्द थे जो तीनों बहनों ने छोड़े थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वे घटना की जांच कई एंगल से कर रहे हैं, जिसमें पीड़ितों की एक कोरियाई ऑनलाइन गेमिंग ऐप की कथित लत भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना में, तीन नाबालिग बहनों ने 4 फरवरी (बुधवार) को सुबह करीब 2:00 बजे एक साथ जान दे दी। उन्होंने टीला मोड़ इलाके की भारत सिटी सोसाइटी में अपने अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। चेतन कुमार की बेटियां, निशिका (16), प्राची (14), और पाखी (12) के शव B1 टावर के फ्लैट 907 के नीचे क्षत-विक्षत हालत में मिले, जिससे सुबह होते ही पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई। "मम्मी, पापा, सॉरी" — ये वे आखिरी शब्द थे जो तीनों बहनों ने छोड़े थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वे घटना की जांच कई एंगल से कर रहे हैं, जिसमें पीड़ितों की एक कोरियाई ऑनलाइन गेमिंग ऐप की कथित लत भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना भारत सिटी इलाके में सुबह 2:15 बजे हुई और पीड़ितों की पहचान निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि बहनें काफी समय मोबाइल फोन पर बिता रही थीं और कथित तौर पर एक कोरियाई ऑनलाइन टास्क-बेस्ड गेमिंग ऐप की आदी थीं। निवासियों ने तेज आवाज सुनने की सूचना दी और अलार्म बजाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एक टीम मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के फ्लैट की तलाशी के दौरान, पुलिस को लड़कियों के माता-पिता के नाम एक पन्ने का नोट मिला, जिसमें लिखा था, "मम्मी, पापा सॉरी।" अधिकारियों ने बताया कि नोट को जांच के हिस्से के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस को अभी यह पुष्टि करनी है कि आत्महत्या ऑनलाइन गेमिंग की लत से जुड़ी है या नहीं और कहा कि मौतों के पीछे का सही कारण अभी भी साफ नहीं है। एसपी सिंह ने कहा, "हमें सूचना मिली कि तीन लड़कियों ने अपनी बिल्डिंग की नौवीं मंजिल की बालकनी से कूदकर जान दे दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। पीड़ितों को लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।" पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है और लड़कियों के मोबाइल फोन और उनकी डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर एक्सपर्ट ऑनलाइन बातचीत और ऐप इस्तेमाल की हिस्ट्री का एनालिसिस करने में मदद कर सकते हैं। तिला मोड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, फॉरेंसिक के लिए फ्लैट को सील कर दिया है और डिजिटल फुटप्रिंट के लिए फोन जब्त कर लिए हैं। एक अधिकारी ने कहा, "क्या उन्हें ऑनलाइन धमकाया गया था, गेम से मैनिपुलेट किया गया था, या पारिवारिक झगड़ों की वजह से ऐसा हुआ? हम गहराई से जांच कर रहे हैं।" यह घटना टीनएजर्स को शिकार बनाने वाले गेमिंग ऐप्स के काले सच को सामने लाती है, और अधिकारी माता-पिता से स्क्रीन पर नज़र रखने का आग्रह कर रहे हैं। दुखी परिवार सदमे में है, गाजियाबाद एक वर्चुअल जाल में फंसी तीन होनहार जिंदगियों के खोने का मातम मना रहा है। शालीमार गार्डन के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अतुल कुमार सिंह ने कहा, "4 फरवरी को, लगभग 2:15 बजे, PRV को सूचना मिली कि फ्लैट नंबर 907, टावर B-1, भारत सिटी, तिला मोड़ पुलिस स्टेशन इलाके में तीन लड़कियों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचने पर, जांच में पीड़ितों की पहचान चेतन कुमार की बेटियों निशिका (लगभग 16 साल), प्राची (लगभग 14 साल), और पाखी (लगभग 12 साल) के रूप में हुई, जिनकी ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से चोटों के कारण मौत हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के 50-बेड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।"

नोएडा: टशन दिखाने को किराए पर ली थार, दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर; बीटेक छात्र गिरफ्तार

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक थार की दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में बीटेक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। चचेरे भाई की शादी में रुतबा दिखाने के लिए किराये पर ली गई थार गाड़ी एक बीटेक छात्र को भारी पड़ गई। तीन दोस्तों के साथ मंगलवार शाम शादी में शामिल होने जा रहे छात्र ने अल्फा-1 सेक्टर में खड़ी आई-टेन कार और एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान युवराज के रूप में हुई है। युवराज ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज में बीटेक का छात्र है। वह अपने तीन दोस्तों के साथ चचेरे भाई की बरात में शामिल होने के लिए ग्रेटर नोएडा से 4500 रुपये में किराये की थार गाड़ी लेकर निकला था। बरात सिरौली, लोनी (गाजियाबाद) की थी। अल्फा-1 सेक्टर में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए युवराज ने सड़क किनारे खड़ी आई-टेन कार और पास में खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद आरोपी थार लेकर मौके से भाग निकला। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पूछताछ में युवराज ने स्वीकार किया कि वह शादी में 'टशन' दिखाने के लिए थार लेकर निकला था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना कर फरार होने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

ललितपुर: शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, दुकानों में तोड़फोड़, सड़क पर फेंकी बोतलें

उत्तर प्रदेश में ललितपुर के महरौनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खितवांस में महिलाओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिलाओं और ग्रामीणों ने दुकानों का ताला तोड़कर अंदर रखी शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक कर नष्ट कर दिया। यह घटना मंगलवार को ललितपुर-महरौनी मुख्य मार्ग पर हुई। जानकारी के अनुसार, महिलाओं ने इस समस्या को लेकर पहले प्रशासन को कई ज्ञापन दिए थे, लेकिन किसी कार्रवाई न होने से उनका सब्र जवाब दे गया। प्रदर्शनकारी न केवल शराब की दुकान का ताला तोड़ते दिखे, बल्कि करीब आधा सैकड़ा से अधिक शराब की पेटियों को सड़क पर फेंककर बोतलें तोड़ दीं। अंग्रेजी शराब की दुकानों में रखी शराब को भी नष्ट किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए गौतम बुद्ध नगर के मुख्यमंत्री डॉ. नरेंद्र कुमार ने शवगृह के नोडल अधिकारी को घटना की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच का आदेश दिया गया है तथा दोषी पाये पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई होगी। घटना की सूचना मिलते ही महरौनी कोतवाली समेत मुख्यालय से भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। सीओ महरौनी रक्षपाल सिंह ने बताया कि मामले में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि प्रकरण में संलिप्त सभी अभियुक्तों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

योगी सरकार का निर्देश: लंबित आवास मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए

उत्तर प्रदेश में वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया है कि सभी लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 (ओटीएस-2026) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी व न्यायसंगत बनाना है। बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित भुगतान और विवादित आवंटन न केवल योजनाओं की प्रगति में बाधा बनते हैं, बल्कि आवंटियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों का समाधान मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई योजना ऐसी हो, जिसमें एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देय राशि में उचित छूट दी जाए। इसके साथ ही, उन लोगों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, जो पूरी राशि एक साथ जमा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि योजना का मूल भाव जनहित होना चाहिए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक जटिलता नहीं होनी चाहिए। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस योजना से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण कई आवंटी निर्धारित समय में भुगतान नहीं कर सके। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए नई योजना को अधिक व्यावहारिक और लचीला स्वरूप देने की आवश्यकता महसूस की गई है।